

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1975
जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लागत वृद्धि

1975. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत/पूर्ण रूप से निर्मित राजमार्गों की राज्य-वार लंबाई किलोमीटर है और पूर्ण/लंबित परियोजनाओं का प्रतिशत कितना है;
- (ख) प्रारंभिक अनुमोदन के समय उक्त परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी थी और वर्तमान संशोधित अनुमानित लागत कितनी है और लागत वृद्धि के क्या कारण हैं;
- (ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी निधि जारी की गई है; और
- (घ) लंबित राजमार्ग खंडों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि और अधिक देरी तथा लागत में वृद्धि की स्थिति से बचा जा सके?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) भारतमाला परियोजना के पहले चरण को सरकार ने 2017 में मंजूरी दी थी, जिसके तहत देश भर में 5.35 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 34,800 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएँ शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत, 8.53 लाख करोड़ रुपये की लागत से कुल 26,425 किलोमीटर लंबी परियोजनाएँ सौंपी गई और 20,770 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है। जून 2025 तक भारतमाला परियोजना के तहत सौंपी गई और निर्मित परियोजनाओं की राज्य-वार लंबाई का व्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे, निर्माण-पूर्व गतिविधियों में देरी, संविदाकारों के समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाइयां, अप्रत्याशित घटनाएँ और निर्माण सामग्री की कमी आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण कुछ परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि हुई है।

इन चुनौतियों से निपटने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए, सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना, तेजी से वन और पर्यावरण मंजूरी की सुविधा के लिए परिवेश पोर्टल का पुनर्निर्माण करना, रेलवे से रोड ऑवरब्रिज (आरओबी) और रोड अंडरब्रिज (आरयूबी) के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन मंजूरी को सक्षम करना, और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल हैं। सरकार इन परियोजनाओं को समय पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

अनुबंध

“भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लागत वृद्धि” के संबंध में श्री रमासहायम रघुराम रेड़ी द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1975 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य	कुल लंबाई (किमी)	सौंपी गई लंबाई (किमी)	जून 25 तक निर्मित लंबाई (किमी)
आंध्र प्रदेश	2,525	1,936	1,234
असम	433	431	349
बिहार	1,572	1,159	698
छत्तीसगढ़	571	471	344
दिल्ली	203	203	187
गोवा	26	26	26
गुजरात	1,577	1,194	1,023
हरियाणा	1,058	1,058	977
हिमाचल प्रदेश	167	167	115
जम्मू और कश्मीर	433	251	145
झारखण्ड	1,000	801	508
कर्नाटक	2,059	1,603	1,156
केरल	1,126	708	506
मध्य प्रदेश	3,063	2,017	1,674
महाराष्ट्र	3,029	2,174	1,944
मणिपुर	635	635	443
मेघालय	170	170	118
मिजोरम	593	593	493
नागालैंड	208	208	153
ओडिशा	1,586	967	928
पंजाब	1,764	1,553	714
राजस्थान	2,503	2,360	2,257
तमिलनाडु	2,414	1,476	1,265
तेलंगाना	1,719	1,026	874
त्रिपुरा	94	94	64
उत्तर प्रदेश	3,126	2,495	2,061
उत्तराखण्ड	273	264	174
पश्चिम बंगाल	874	385	339
कुल	34,800	26,425	20,770
